वीबीग्रामजी रद्द करो, मनरेगा बहाल करो
Repeal VBGRAMG, bring back MGNREGA

(Scroll below the Hindi text to read the English translation)

15 फ़रवरी 2026

हम, नीचे दस्तखत करने वाले एक्टिविस्ट्स, जो भारत के कोने-कोने में मनरेगा मजदूरों के साथ काम करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करने की कड़ी निंदा करते हैं, जो माँग पर मिलने वाला 'काम के अधिकार' का प्रोग्राम था।

हमने समझा है कि:

- मनरेगा महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना से सीख लेकर भारी समर्थन और बातचीत के बाद शुरू किया गया था।

- पहली बार हर परिवार को 100 दिन का काम मिलना पक्का किया गया था।

- जाति और जेंडर के भेदभाव को मिटाकर, गांव के मजदूरों को वर्ग के आधार पर अपनी यूनियन बनाने का मौका मिला । मनरेगा के आने से, उदाहरण के लिए कर्नाटक में 'ग्राकुस' नाम की एक लाख मेंबर वाली गाँव के मजदूरों की यूनियन बनी । ये मजदूरों की यूनियन बनाने का एक ज़रिया बन गया।

- बुवाई और कटाई के वक़्त खेतिहर मजदूरों को मोलभाव करने की ताक़त मिली।

- इसके चलते कई लोगों, खासकर औरतों ने पहली बार बैंक खाते खुलवाए, बैंक गईं और पैसे निकाले ।

- गांव की औरतें, जो घर की चहारदिवारी में बंद थीं, उन्हें एकजुट होकर अपनी हालत सुधारने पर बात करने और अपने गाँव से लेकर देश की राजधानी तक अपनी माँगें उठाने का मौका मिला । **2026** के इकनॉमिक सर्वे के हिसाब से, **2025** में **187** करोड़ मजदूरों में से **58%** औरतें थीं।

- कई जगहों पर पहली बार मर्दों और औरतों को बराबर मजदूरी मिली।

- कोविड की महामारी के दौरान यह कामकाजी लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा था।

- ग्राम सभा को ये हक मिला कि वो अपने इलाके के सार्वजनिक कार्यों का प्लान और बजट बनाएं, लोगों को एक साथ बैठकर बात करना सिखाया, और पानी बचाने के इंतजामों का एक नेटवर्क बनाया जिससे सूखे से बचने में मदद मिली।

- जिन ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन मैनेजमेंट का अधिकार मिला हुआ था, उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तालमेल में मनरेगा को चलाने वाली एजेंसियां बनाया गया।

- छोटे किसानों को सब्जी की खेती और मछली पालन करके अपनी आय बढ़ाने में मदद मिली।

- जब उन्हें कोई काम नहीं मिला तब बेरोजगारी भत्ता मिला, जिसका फायदा कम से कम संगठित मज़दूर ले पाए।

- मिट्टी और पानी को बचाने का बहुत जरूरी काम हुआ।

- सरकारी अध्ययनों में भी इसे एक बढ़िया प्रोग्राम बताया गया।

- अगर भ्रष्टाचार या अमलीकरण में गड़बड़ी या स्टाफ की कमी वगैरह इस एक्ट को खत्म करने की वजहें थीं, तो सरकार का पहला फ़र्ज़ था कि वो ग़लत काम रोके और कामकाज में जो कमी है उसे दूर करे, जिसमें अक्सर सरकारी अफसरों की मिलीभगत होती है।

- केंद्र सरकार ने लगातार और जानबूझकर अपना हिस्सा नहीं दिया, जिससे मजदूरी देने में देरी हुई।

- डिजिटलीकरण और ई-केवाईसी के चक्कर में लाखों मजदूर अपना रोज़गार खो बैठे । पारदर्शिता के नाम पर मोबाइल ऐप, जियो-टैगिंग, केवाईसी के द्वारा आधार से जोड़ना शुरू किया गया, लेकिन इससे कई मजदूरों के जॉब कार्ड रद्द हो गए और उन्हें बाहर कर दिया गया।

हम इस दलील को एक सिरे से ख़ारिज़ करते हैं कि मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए वीबीग्रामजी बनाया गया है,

- वीबीग्रामजी में माँगने पर काम नहीं मिलेगा, सिर्फ सरकार बताएगी वहीं काम मिलेगा।

- खेती के मौसम में खेतिहर मजदूरों की दिहाड़ी कम हो जाएगी क्योंकि **60** दिन काम नहीं मिलेगा।

- ज़मींदारों और पोलिटिकल नेताओं ने मनरेगा का विरोध किया, जिन्होंने इसमें अपनी ताकत

के लिए खतरा देखा । इसे खत्म करने का विचार तब आया जब इन्होंने देखा कि इसका इस्तेमाल मजदूरों, खासकर औरतों को अपनी यूनियन बनाने के लिए किया जा रहा है । ये इसलिए भी हटाया जा रहा है ताकि मजदूरी कम की जा सके और पूँजीपतियों को सस्ते मजदूर मिल सके।

- भाजपा मनरेगा की शक्ति के खिलाफ है, जैसे कि काम का असली हक मिलना, विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना, वर्ग के आधार पर गांव के मजदूर अपनी यूनियन बनाना, और नारीशक्ति मजबूत बनाना । कुल मिला कर समाज में जड़ से बदलाव हो, वह उसे रास नहीं आता।

- ठेकेदार पहले मनरेगा में चोरी-छिपे घुस रहे थे, हालांकि, इसमें प्रतिबंध था । वीबीग्रामजी अब ठेकेदारों के काम को कानूनी बना देगा, क्योंकि इसमें आमूल ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा।

- वीबीग्रामजी में सब कुछ ऊपर से तय होगा, ग्राम सभा की भूमिका बस नाम की रह गई है।

- भ्रष्टाचार तो रहेगा ही क्योंकि सरकारी अफसर इससे सने हुए हैं, और सरकार के पास इससे निपटने के लिए बहुत वक़्त था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया । प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने और वर्कप्लेस की जियोटैगिंग करने के बाद भी, इससे बचने के तरीके खोज लिए गये हैं, जैसे कि मजदूरों को एक ही दिन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।

हमें डर है कि मनरेगा को खत्म करने और वीबीग्रामजी को लागू करने से -

- गाँव में रोजगार घट जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पहले से ही वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए 'अनटाईड' फंड कम है।

- झारखंड जैसे राज्यों में, ख़ासकर खेती के मौसम के उन **60** दिनों में जब वीबीग्रामजी के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा, तब बंधुआ मजदूरी बढ़ेगी, गांव में दिक़्क़तें बढ़ेंगी, जिसमें भूखमरी फैलेगी और मजबूरी में पलायन बढ़ जाएगा।

- जब औरतों को भी पलायन करना पड़ेगा, तो बच्चों का स्कूल छूट जाएगा और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा।

- वीबीग्रामजी लाभार्थी के माईबाप जैसी स्कीम बन जाएगी, और जिन राज्यों में चुनाव होंगे उन्हें केंद्र से ज्यादा पैसा मिलेगा । जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं वे फंड के लिए तरसते रह जाएंगे।

- हर परिवार को **125** दिन का काम देने का वादा एक हवा-हवाई दावा बनकर रह जाएगा और

हर परिवार को मिलने वाले काम के दिनों की औसत संख्या वास्तव में घट जाएगी क्योंकि **40** प्रतिशत खर्च करना राज्यों के बस की बात नहीं होगी क्योंकि वे तो वैसे ही कर्ज़ में डूबे हुए हैं।

हम संकल्प लेते हैं कि:

- ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कराएंगे, बार-बार मार्च और प्रदर्शन आयोजित कराएंगे, और अपने चुने हुए प्रतिनिधि पर दबाव डालेंगे कि वह वीबीग्रामजी को रद्द कर के मनरेगा को बहाल करने की माँग करें।

1. **सुरेश राठौड़**, **मनरेगा मजदूर यूनियन**, **उत्तर प्रदेश**

2. **सीमा काकड़े**, **कल्पवृक्ष**, **महाराष्ट्र**

3. **दिलीप कामत**, **ग्रामीण कूलिकारा संघ**, **कर्नाटक**

4. **पीएम टोनी**, **बगइचा**, **रांची**, **झारखंड**

5. **शनियारो देवी**, **नरेगा मजदूर सहायता केंद्र**, **लोहरदगा**, **झारखंड**

6. **अजय आशु**, **क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन**, **हरियाणा**

15 February, 2026

We, the undersigned activists working with MGNREGA workers in various parts of India condemn the repeal of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), a demand-based 'Right to work' programme. We, hereby,

Observe that MGNREGA:

- Was enacted after much mobilization and discussion, learning from the experience of Maharashtra's Employment Guarantee Scheme.

- Guaranteed 100 days of employment for every household for the first time.

- Offered the opportunity of creating class-based organisations of rural workers, overcoming the divisiveness of caste and gender. For example, the enactment of MGNREGA resulted in the creation of GRAKOOS, a one-lakh member rural workers' organization in Karnataka. It became an instrument to build workers' organizations.

- Gave bargaining power to agricultural labourers in the sowing and harvesting season.

- Resulted in many people, and especially women, opening bank accounts for the first time, visiting banks and withdrawing money.

- Enabled rural women who had been confined in their homes and villages to come together and discuss how to improve their situation, and raise demands, right from their own villages to the national capital. Economic Survey 2026 records that 58% were women workers out of 187 crores in 2025.

- Provided equal wages to men and women, for the first time in many places.

- Was the greatest support for working people during the COVID pandemic.

- Gave autonomy to the Gram Sabha to plan and budget for local public work, teaching people to sit together and discuss, and resulting in a network of water harvesting measures that contributed to drought-proofing.

- In convergence with FRA, made Gram Sabhas whose Community Forest Resource management rights had been recognized, implementing agencies of MGNREGA.

- Enabled small landholders to augment their income through vegetable cultivation and fish farming.

- Provided an unemployment allowance which at least organized groups of people were able to avail when no work was provided.

- Facilitated much-needed conservation of soil and water.

- Was shown to be an effective programme by several Government studies.

- If the corruption or lacunae in implementation or shortage of staff etc were the reasons to repeal the Act, it was government's primary duty to prevent malpractices and address the lack of efficient operationalisation that often involved government officials.

- The Central Government consistently and deliberately failed to release its share which resulted in the delay in payment of wages.

- Digitalisation and e-KYC processes resulted in lakhs of workers losing employment. Mobile-based apps, geo-tagging, KYC-based Aadhaar-linking were introduced in the name of transparency, but resulted in the exclusion of many workers through deletion of their job cards.

Reject the justification that VBGRAMG was enacted to overcome the deficiencies of MGNREGA:

- VBGRAMG is not demand-based, work will be provided only in areas notified by the Government.

- Work suspension for 60 days in the peak agricultural season will depress wages of agricultural labourers.

- MGNREGA was opposed by landlords and political leaders who saw it as a threat to their own power. The idea to repeal it arose after seeing how it was being used as a tool to organize workers, and especially women workers. It has also been done to depress wages and to make cheap labour available for capitalists.

- The BJP is opposed to the potential that MGNREGA offered, to obtain a genuine right to work, strengthen decentralization, create class-based rural workers' organisations, and strengthen feminism; in short, for fundamental transformation of society.

- Contractors were earlier making a back-door entry into MGNREGA, where they are officially banned. With its infrastructure focus, VBGRAMG will now make their involvement official.

- Planning under VBGRAMG is effectively top-down, the role of the Gram Sabha has been made nominal.

- Corruption will continue as it is Government officials who indulge in it, and though the Government had ample time to tackle it, did not do so. Even with digitalization of processes and geotagging of worksites, ways have been found to bypass it, e.g. by transporting workers from one site to another on the same day.

Apprehend that the repeal of MGNREGA and the provisions of VBGRAMG will lead to:

- Reduced rural employment, as State Governments have fewer untied funds already to meet welfare provisioning.

- Increased labour bondage, increased rural distress, including starvation and distress-migration, especially in states like Jharkhand, and especially in the 60 days of the agricultural season when no work will be provided under VBGRAMG.

- Children going out of school or their education suffering, when women are also forced to migrate.

- VBGRAMG becoming a beneficiary-oriented patronage programme, with states going to elections getting higher allocations from the Centre. States with non-BJP

governments will be starved of funds.

- The promised 125 days of work per household remaining a mirage, and the average number of workdays per household actually decreasing, as debt-strapped states will be unable to spend 40 percent of expenditure.

Resolve to:

- Pass Gram Sabha resolutions, repeatedly organize marches and demonstrations, and pressurise local elected representatives to demand the withdrawal of VBGRAMG and revive MGNREGA.

1. Suresh Rathaur, MGNREGA Mazdoor Union, Uttar Pradesh

2. Seema Kakade, Kalpavriksh, Maharashtra

3. Dileep Kamat, Grameena Koolikara Sangha, Karnataka

4. PM Tony, Bagaicha Social Centre, Ranchi, Jharkhand

5. Shaniyaro Devi, NREGA Mazdoor Sahayata Kendra, Lohardaga, Jharkhand

6. Ajay Ashu, Krantikari MNREGA Mazdoor Union, Haryana

Endorsed by:

Organisations:
1. Rajesh Ramakrishnan, Campaign to Defend Nature and People (CDNP)
2. Arvind Murti, Indian Community Activists Network (ICAN)
3. Geeta Mahajan, National Federation of Indian Women (NFIW)
4. Viren Lobo, Akhil Bharatiya Mazdoor Kisan Sangharsh Samiti (ABMKSS)
5. Prasad Chacko, People's Union for Civil Liberties (PUCL)
6. Meera Sanghamitra, National Alliance of People's Movements (NAPM)
7. Manthan, Jan Mukti Sangharsh Vahini
8. Sushil Kumar, Jan Mukti Sangharsh Vahini
9. Subhash Lomte, National Campaign Committee for Rural Workers (NCCRW); Jai Kisan Andolan; Swaraj Abhiyan
10. Tapan Padhi, Mission Justice
11. Shashi Shekhar Singh, Citizens for Democracy
12. Dipak Dholakia, Campaign to Defend Nature and People (CDNP)
13. Nootan, Campaign to Defend Nature and People (CDNP)
14. Mahendra Rathaur, Indian Community Activists Network (ICAN)
15. Monisha Rao, India Friends Association, USA
16. Dasharath Jadhav, Shramjivi Sangathana Marathwada, Maharashtra
17. Gufran, People's Alliance, Uttar Pradesh

18. Ashish Ranjan, Jan Jagran Shakti Sangathan, Bihar
19. Shankar Gopal, Chetna Andolan, Uttarakhand
20. Indra Narayan Singh, Kosi Nav Nirman Manch, Bihar
21. Gopinath Majhi, Campaign for Survival and Dignity, Odisha
22. Chhaya Datar, Mahila Kisan Adhikar Manch (MAKAAM), Maharashtra
23. Raj Kumar Sinha, Bargi Bandh Visthapit Evam Prabhavit Sangh, Madhya Pradesh
24. Dr. Sricharan Behera, Campaign for Survival and Dignity, Odisha
25. Ambika Yadav, Jharkhand Kisan Parishad, Jharkhand
26. Praveer Peter, Sajha Kadam, Jharkhand
27. Ranjana Kanhere, Lokshahi Jagar Samiti, Nandurbar, Maharashtra
28. Raviraj Mankar, Labour Study and Research Centre, Wardha, Maharashtra
29. Sharada Gopal, Jagruta Mahila Okkuta, Belgaum, Karnataka
30. Sujata Gothoskar, Nari Atyachar Virodhi Manch, Mumbai, Maharashtra
31. Jagmohan Singh, Association For Democratic Rights, Ludhiana, Punjab
32. Kiran, Sanbhava Injor, Ranchi, Jharkhand

Individuals

33. Seema Kulkarni, Pune, Maharashtra
34. Ravi Chopra, Dehra Dun, Uttarakhand
35. Usha Rao, Chikkaballapur, Karnataka
36. Jyotsna Tirkey, West Singhbhum, Jharkhand
37. Nandita, Pune, Maharashtra
38. Pradeep Chavan, Maharashtra
39. Suresh Khole, Pune, Maharashtra
40. Ujjwala, Maharashtra
41. Chinmayee
42. Chetan, Maharashtra
43. Ramnarayan K., Uttarakhand
44. Kanupriya, Chandigarh
45. James Herenj, Jharkhand
46. Savita Tare, Maharashtra
47. Varsha Mehta, Ahmedabad, Gujarat
48. Mohammed Ishak, Nainital, Uttarakhand
49. Mehjabeen, Haridwar, Uttarakhand
50. Meena, Kutch, Gujarat
51. Adv Dr. Shalu Nigam, Delhi NCR
52. K.J. Joy, Pune, Maharashtra
53. Sunil M. Caleb, Kolkata, West Bengal
54. Suhas Kolhekar, Maharashtra
55. Kavita Gandhi
56. Jagriti Rahi, Varanasi, Uttar Pradesh